

क्या पानी का संकट हमें ले डूबेगा?

एक अनुमान के मुताबिक, यदि पानी के उपयोग की वर्तमान रीति-नीति जारी रही तो वर्ष 2030 तक दुनिया में पानी की खपत 20 खरब घन मीटर बढ़कर 69 खरब घन मीटर हो जाएगी। यह खपत उपलब्ध जल स्रोतों से पूरी करना नामुमकिन होगा। वास्तव में, यह उपलब्ध क्षमता से 40 प्रतिशत ज्यादा है। सवाल है कि इस संदर्भ में क्या किया जा सकता है।

श्रीलंका के बतारमुला के अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान के शोधकर्ताओं ने इस संकट को टालने के लिए एक योजना तैयार की है। योजना बनाने वाले शोधकर्ताओं में संस्थान के निदेशक कोलिन चार्टर भी शामिल हैं।

फिलहाल पानी का सर्वाधिक उपयोग कृषि में होता है। कई देशों में तो पानी की कुल खपत में से 70-90 प्रतिशत खेती में खर्च होता है। चार्टर का कहना है कि इसे बदलना होगा। कारण यह है कि अगले चालीस वर्षों में दुनिया की आबादी का पेट भरने के लिए आज के मुकाबले खाद्यान्न का उत्पादन दुगना करना ज़रूरी होगा।

यदि पानी के उपयोग में परिवर्तन न किया गया तो चालीस साल बाद की मांग की पूर्ति असंभव होगी। यदि सारा पानी खेती और उद्योगों में खप गया तो जलीय पर्यावरण के लिए कुछ न बचेगा, नदियां सूख जाएंगी।

दिवक्कत यह है कि राष्ट्रों की पानी-उपयोग की योजनाएं उस दौर में बनी थीं जब पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध था।

भारत जैसे विकासशील देशों ने सतही सिंचाई का रास्ता अपनाया था जिसमें पानी गुरुत्व बल की बदौलत बहता है। मगर अब ये तंत्र नाकाफी साबित हो रहे हैं और किसान बढ़ते क्रम में भूजल का उपयोग कर रहे हैं। सरकारें भूजल निष्कासन का कोई नियमन नहीं करती हैं जिसकी वजह से कई इलाकों में भूजल स्तर नीचे खिसकता जा रहा है।

सरकारों को पानी उपयोग की नीतियों में कृषि व उद्योगों का ख्याल करना होगा और उन्हें पानी आवंटित करना होगा। मगर यहां एक दिक्कत आंकड़ों के अभाव की है। चार्टर का मत है कि 1980 के दशक से पानी के निजीकरण के कारण आंकड़ों का घोर अभाव पैदा हो गया है क्योंकि निजी कंपनियां जानकारी एकत्रित करने या पानी के उपयोग की निगरानी वगैरह पर ज्यादा ध्यान नहीं देतीं। इसका मकसद पैसा बचाना होता है। अलबत्ता, अब शायद उपग्रह सूचनाओं की मदद से आंकड़ों की कमी को दूर किया जा सकेगा।

चार्टर का मत है कि संकट तक पहुंचने से पहले हम ऐसी टेक्नॉलॉजी का उपयोग शुरू कर सकते हैं जिससे मांग व आपूर्ति के बीच की खाई कम हो। इनमें सिंचाई की बेहतर टेक्नॉलॉजी, और उद्योगों में पानी की खपत को कम करना वगैरह शामिल हैं। एक सुझाव यह भी है कि गंदे पानी को रीसायकल किया जाए। इससे उद्योगों की मांग को कम करने में मदद मिलेगी। (स्रोत फीचर्स)